

# कशोर न्याय कानून : चुनौतियाँ एवं समाधान

## किशोर न्याय कानून : चुनौतियाँ एवं समाधान

### 1. पृष्ठभूमि

- अखिल भारतीय स्तर पर एकदमजान बाल अधिनियम लागू करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा 1986 में एक किशोर न्याय अधिनियम पारित किया गया

### 2. मुख्य प्रावधान

- 16 वर्ष से कम आयु के लड़के व 18 वर्ष से कम आयु की लड़की द्वारा किये गए कानून विरोधी कार्यों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया
- अपराधियों हेतु अलग से किशोर अपराध न्यायालय की स्थापना

### 3. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवंबर, 1989 को बाल अधिकार अधिनियम अपनाया गया, भारत ने भी इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किये हैं।
- संशयतः इसी वर्ष 2000 में किशोर न्याय कानून, 1986 में संशोधन कर लड़कों के संदर्भ में आयु सीमा को बढ़ाकर 16 से 18 वर्ष कर दिया गया क्योंकि अधिनियम के अनुसार 18 साल से कम के किशोरों को नबालिन ही माना जाता है।

### 4. संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015

- प्रथम अपराध करने की स्थिति में बाल अपराधी की आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष किया गया है।
- पहली बार अपराधों की श्रेणी निर्धारित की गई और प्रथम अपराध को भी परिभाषित किया गया, जिस अपराध में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है, उसे प्रथम अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जैसे- हत्या, बलात्कार आदि।
- इसमें गैर-कानूनी तौर पर बच्चा गोद लेने, अंतर्कवासी समूहों द्वारा बच्चों का दुरूपचार करने और विकलांग बच्चों को विरुद्ध अपराधों जैसे नए अपराधों को भी शामिल किया गया।

### 5. न्याय कानून कितना तर्कसंगत?

- पहला सवाल, क्या प्रस्तावित कानून बाल अधिकारों पर बने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिनियम का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र अधिनियम का अनुच्छेद (1) 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को बाल अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है।
- दूसरा सवाल, क्या कानून जेंडर न्यूट्रल है या सिर्फ लड़कों पर लागू होगा? संगीन युग के माजलों में लड़कों को 16 साल की आयु में सख्त सजा का प्रयोजन किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि वर्तमान में लड़के-लड़कियों के अपराध का अनुपात 70:30 है।
- एक तर्क यह है कि प्रथम अपराध करने वाले नबालिन अपराधियों पर वयस्कों की तरह कैस चलाने से संशोधन के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होता है। लेकिन विचारणीय तथ्य यह है कि मौलिक अधिकार भी अस्वीकृत नहीं हैं बल्कि उन पर भी युचितयुक्त विवेचन लगाए गए हैं।

### 6. समस्याएँ

- किशोरों के मानसिक अटकल के लिये हमारा समाज और विभागत सामाजिक माहौल बराबर के जिम्मेदार है।
- संयुक्त परिवार के विखंडन के कारण बच्चे परंपरागत पावन-पोषण से दूर हो गए हैं।
- आधुनिक संचार के युग में बच्चे अब बहुत जल्दी परिपक्व तो हो रहे हैं, लेकिन उन्हें आवश्यक सामाजिक मूल्यों, नैतिकता और मानवता का ज्ञान नहीं मिल पाता है।

### 7. समाधान

- नैतिक शिक्षा कठोर दंड से नहीं बल्कि प्रेम से ही सिखाई जा सकती है और इसकी शुरुआत प्रथम पाठशाला वाली घर और आसपास के समाज से ही संभव है।
- बढ़ते बाल अपराध का केवल राजनीतिक और यंत्रणात्मक समाधान नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिये मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक समाधान ज़रूरी कारगर हैं।
- मनोवैज्ञानिक सहायता से अभिभावकों तथा अध्यापकों को यह देखा जाना चाहिए कि बच्चे के अपराधी आचरण की समाप्ति हेतु और क्या कारगर उपाय किये जा सकते हैं।